नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 219
दि. 13.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तमिलनाडु की सत्ता पर सियासी संग्राम तेज

तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण से पहले राज्य का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और सत्ता के गलियारों में जोड़-तोड़, समर्थन और बगावत का खेल खुलकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बहुमत साबित करने की है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी दलों और सहयोगी गुटों के बीच भी अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। तमिल राजनीति में लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है, लेकिन अब टीवीके के उभार ने पूरे सियासी समीकरण को बदल दिया है। यही कारण है कि फ्लोर टेस्ट से पहले हर दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को एआईएडीएमके के बागी नेताओं एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ा दी। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इन दोनों नेताओं के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनके साथ लगभग 30 विधायक हैं, जो विधानसभा में विजय सरकार के समर्थन में मतदान कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में यह एक बड़ा मोड़ साबित होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल समर्थन जुटाने की कोशिश नहीं, बल्कि एआईएडीएमके के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का भी संकेत है।

टीवीके प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही कई दलों का समर्थन हासिल कर लिया था। कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे सहयोगी दल पहले से ही उनके साथ खड़े हैं। इसके बावजूद सरकार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण विधानसभा में होने वाला बहुमत परीक्षण है, जहां एक-एक विधायक का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि अंतिम क्षणों तक समीकरण बदलते रहते हैं और यही स्थिति इस बार भी दिखाई दे रही है।

एआईएडीएमके के भीतर मचे घमासान ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। एसपी

वेलुमणि और सीवी षणमुगम द्वारा विजय को समर्थन देने की खुली वकालत को पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह गुट अलग होता है तो एआईएडीएमके में बड़ी टूट संभव है। इससे न केवल पार्टी कमजोर होगी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में उसकी पकड़ भी कमजोर पड़ सकती है। लंबे समय से राज्य की राजनीति में प्रभावशाली रही एआईएडीएमके अब अंदरूनी संघर्ष से जूझती दिखाई दे रही है।

तमिल राजनीति में यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय दलों के भीतर नेतृत्व को लेकर लगातार असंतोष बढ़ता रहा है। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी नेतृत्व उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा। यही कारण है कि अब विधायक खुलकर अपनी अलग राजनीतिक दिशा तलाशने लगे हैं। टीवीके के उभार ने भी कई नेताओं को नया विकल्प दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय की लोकप्रियता युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच तेजी से बढ़ी है और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जा रही है।

इसी बीच अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम यानी एएमएमके में भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। पार्टी महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने अपनी पार्टी के इकलौते विधायक एस कामराज को पार्टी से बाहर कर दिया। कामराज ने विजय सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में कामराज विजय के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस समय निष्ठा और समर्थन के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

मुख्यमंत्री विजय लगातार अपने सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं से भी बैठक की, जिन्होंने बिना किसी शर्त के सरकार को समर्थन देने का भरोसा दिया है। कांग्रेस के पांच विधायक, सीपीआई और सीपीएम के विधायक भी पहले से विजय सरकार के साथ खड़े हैं। हालांकि राजनीति में केवल समर्थन का दावा पर्याप्त नहीं होता, असली परीक्षा विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में होती है, जहां यह तय होगा कि सत्ता पर किसका नियंत्रण रहेगा।

तमिलनाडु विधानसभा में होने वाला बहुमत परीक्षण केवल सरकार बचाने का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। यदि विजय सरकार बहुमत साबित करने में सफल रहती है, तो टीवीके राज्य की राजनीति में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगी। दूसरी ओर यदि सरकार असफल होती है, तो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। ऐसे में सभी दल पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं।

इस राजनीतिक संघर्ष के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। टीवीके विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फ्लोर टेस्ट में भाग लेने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम Court ने इस मामले में सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई की तारीख तय की। इस कानूनी लड़ाई ने भी तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय तक करिश्माई नेताओं के इर्द-गिर्द घूमने वाली राजनीति अब नए चेहरों और नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। विजय का उभार इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ने युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि पारंपरिक दलों के कई नेता भी उनके साथ आने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से नाटकीय घटनाक्रमों और अचानक बदलते समीकरणों के लिए जानी जाती रही है। यहां सत्ता का संघर्ष केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता की भावनाओं, क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ा होता है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरह से दल-बदल, समर्थन और विरोध का दौर चल रहा है, उसने पूरे राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।

अब सबकी नजर बुधवार को होने वाले बहुमत परीक्षण पर टिकी हुई है। यह केवल सरकार की परीक्षा नहीं, बल्कि तमिलनाडु की नई राजनीतिक दिशा का फैसला भी होगा। यदि विजय बहुमत साबित करने में सफल रहते हैं, तो यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत होगी। वहीं विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। दूसरी ओर यदि बहुमत का आंकड़ा उनके हाथ से निकलता है, तो राज्य में एक नए राजनीतिक संकट की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में हर पल नया मोड़ सामने आ रहा है और आने वाले दिन राज्य की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं।

गुवाहाटी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एनसी हिल्स परिषद का दलबदल विरोधी नियम रद्द

पूर्वोत्तर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद द्वारा पारित 42वें संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले को स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक अधिकारों और दलबदल विरोधी कानून की सीमाओं के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की पीठ ने 7 मई को यह आदेश पारित किया, जिसके बाद दीमा हसाओ जिले की राजनीतिक व्यवस्था और परिषद की कार्यप्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

यह मामला दीमा हसाओ जिले के कुछ निवासियों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा हुआ था, जिसमें एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद (42वां संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत बनाए गए नियम 18ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह नियम परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अधिकारों को अनुचित रूप से सीमित करता है और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया।

नियम 18ए के तहत प्रावधान किया गया था कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के व्हिप या निर्देश के खिलाफ मतदान करता है या मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित रहता है, तो उसे भी अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। इस नियम का उद्देश्य परिषद में अनुशासन और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना बताया गया था, लेकिन अदालत ने इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर का कानून करार दिया।

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद को इस प्रकार का दलबदल विरोधी कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी भी निकाय द्वारा बनाया गया कानून संविधान और उसके मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए, और यदि कोई प्रावधान नागरिकों या निर्वाचित प्रतिनिधियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे बनाए नहीं रखा जा सकता। अदालत के अनुसार यह नियम न केवल असंवैधानिक था, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मूल भावना के भी खिलाफ था।

इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव स्थानीय स्वायत्त परिषदों की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है। एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद जैसे निकायों को सीमित प्रशासनिक और विधायी अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उनके कानून बनाने की शक्ति संविधान के दायरे में ही होती है। अदालत के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वायत्त निकाय भी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ऐसे नियम नहीं बना सकते जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित करें।

यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन का भी उदाहरण बन गया है। दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधियों के विवेक पर असर डाल सकता है। इसी संतुलन को लेकर अदालतों में समय-समय पर बहस होती रही है। गौरतलब है कि भारत में दलबदल विरोधी कानून 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था। लेकिन समय के साथ यह सवाल उठता रहा है कि क्या यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह फैसला इसी व्यापक बहस का हिस्सा माना जा सकता है।

दीमा हसाओ जैसे जनजातीय और स्वायत्त क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासनिक निकायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वे अपने क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकें। लेकिन इन अधिकारों की भी एक संवैधानिक सीमा होती है। अदालत ने अपने निर्णय में यही संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है कि स्वायत्तता का मतलब मनमानी शक्ति नहीं है। इस फैसले के बाद अब एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद को अपने नियमों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अन्य स्वायत्त परिषदों और स्थानीय निकायों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जो भविष्य में अपने कानून बनाते समय संवैधानिक सीमाओं का अधिक ध्यान रखेंगे। स्थानीय राजनीति पर भी इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है। दलबदल विरोधी नियम के खत्म होने से परिषद के भीतर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और सदस्य अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने की स्थिति में आ सकते हैं। हालांकि इससे परिषद में अस्थिरता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर, गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह निर्णय केवल एक कानून को रद्द करने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे, स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कूनो नेशनल पार्क में दर्दनाक घटना, चार नवजात चीता शावकों की मौत से बढ़ी चिंता

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को गहरा झटका लगा है, जहां मात्र एक महीने पहले जन्मे चार चीता शावकों की मंगलवार सुबह मौत हो गई। यह घटना उस समय सामने आई जब मॉनिटरिंग टीम नियमित निरीक्षण के लिए मां चीता केजीपी-12 के मांद के पास पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, शावकों के शव आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त और खाए हुए अवस्था में मिले, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत किसी जंगली शिकारी के हमले के कारण हुई है। हालांकि, वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा।

जानकारी के अनुसार, इन चारों शावकों का जन्म 11 अप्रैल को हुआ था और उन्हें कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के तहत संरक्षित रखा गया था। यह भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही थी, क्योंकि इन शावकों का जन्म देश में जन्मे चीतों की नई पीढ़ी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन 11 मई की शाम के बाद से इन्हें जीवित नहीं देखा गया था, और मंगलवार सुबह उनके शव मिलने से पूरे वन्यजीव संरक्षण समुदाय में शोक की लहर फैल गई।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग साढ़े छह बजे मॉनिटरिंग टीम को सूचना मिली कि श्योपुर क्षेत्र में स्थित मां चीता केजीपी-12 के डेन के पास संदिग्ध स्थिति है। जब टीम मौके पर पहुंची, तो चारों शावक मृत अवस्था में पाए गए। प्रारंभिक निरीक्षण में यह सामने आया कि शवों पर किसी अन्य जंगली जानवर के हमले के संकेत मिले हैं। हालांकि, यह भी जांच का विषय है कि हमला कब और कैसे हुआ तथा क्या इसमें किसी अन्य कारण की भी भूमिका रही।

इस घटना के बाद मादा चीता पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वह अपने प्राकृतिक व्यवहार में सामान्य रूप से सक्रिय है और उसमें किसी प्रकार की चोट के संकेत नहीं मिले हैं। यह तथ्य जांच को और जटिल बनाता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमला मां चीता की मौजूदगी में हुआ या किसी अन्य परिस्थिति में।

कूनो नेशनल पार्क में यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह भारत में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के लिए एक बड़ा झटका है। अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत में पुनः बसाने की यह महत्वाकांक्षी योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके एशियाई चीते की उपस्थिति को फिर से स्थापित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना है।

इन चार शावकों की मौत के बाद अब भारत में कुल चीतों की संख्या 53 रह गई है। इनमें से 50 चीते कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं, जिनमें 33 चीते भारत में जन्मे हैं। इसके अलावा तीन चीते गांधी सागर अभयारण्य में रखे गए हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि परियोजना अभी शुरुआती और संवेदनशील चरण में है, जहां हर प्राकृतिक घटना का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि नवजात शावकों की मृत्यु कई कारणों से हो सकती है, जिनमें प्राकृतिक शिकारी, पर्यावरणीय परिस्थितियां, या मां की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी शामिल हो सकती है। हालांकि, कूनो जैसे संरक्षित क्षेत्र में ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं, इसलिए इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है।

वन विभाग ने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और विशेषज्ञों की टीम को मौके पर भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि शावकों की मौत का वास्तविक कारण क्या था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या पार्क की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक हुई थी या नहीं।

कूनो नेशनल पार्क पहले भी चीता परियोजना को लेकर चर्चा में रहा है। यहां लाए गए चीतों के अनुकूलन और संरक्षण को लेकर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। हालांकि, प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, खासकर नवजात शावकों के लिए, जिनकी सुरक्षा पूरी तरह मां और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है।

इस घटना ने एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण की जटिलताओं को उजागर कर दिया है। भले ही इंसानी प्रयासों से प्रजातियों को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन प्रकृति के नियम और जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र अपनी कठोर वास्तविकताओं के साथ काम करता है। ऐसे में हर छोटी घटना भी बड़े परिणामों का कारण बन सकती है।

पॉक्सो केस से तेलंगाना की राजनीति में भूचाल

तेलंगाना की राजनीति में मंगलवार को उस समय बड़ा भूचाल आ गया, जब केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे भागीरथ ने एक पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी हलकों तक हलचल मचा दी है। भागीरथ ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के साथ-साथ अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की भी मांग की है। मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और विपक्षी दलों ने सरकार तथा भाजपा दोनों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

यह पूरा मामला आठ मई को दर्ज हुई एक शिकायत से जुड़ा है। शिकायत एक 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि भागीरथ का उसकी बेटी के साथ संबंध था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच कथित संबंध लगभग सात से आठ महीने पहले शुरू हुआ था। शिकायत सामने आने

के बाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और जांच एजेंसियां हर पहलू को गंभीरता से देख रही हैं। भागीरथ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह मामला पूरी तरह से झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने किशोरी और उसके माता-पिता पर जबरन वसूली तथा आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट से राहत की मांग की है। उनके वकीलों का तर्क है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिना पर्याप्त साक्ष्यों के गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई उचित नहीं होगी।

दूसरी ओर, शिकायत दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद को मामले की जांच तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष जांच टीमें गठित करने को कहा है, ताकि मामले की हर पहलू से जांच की जा सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। सरकार का कहना है कि नाबालिग से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटनाक्रम के बाद तेलंगाना की राजनीति में माहौल और गर्म हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बन चुका है। केंद्रीय मंत्री के परिवार का नाम सामने आने के कारण यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार तेलंगाना भाजपा के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और भाजपा के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उनके बेटे पर लगे आरोपों ने राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित किया है। विपक्षी दल इस मामले को भाजपा की नैतिकता से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अदालतें बेहद सावधानी बरतती हैं। चूंकि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए इसमें जांच प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान काफी सख्त हैं। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत मिलना आसान नहीं माना जाता, लेकिन अदालत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि भागीरथ को अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में भागीरथ ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रेरित है और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, फोन रिकॉर्ड और अन्य संबंधित जानकारियों को भी खंगाल रही हैं।

मामले ने सोशल मीडिया पर भी व्यापक बहस छेड़ दी है। एक ओर लोग नाबालिग से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और यह मामला राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

तेलंगाना में पिछले कुछ समय से राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर पहले से ही जारी था, लेकिन अब इस मामले ने राजनीतिक तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक गूंज सकता है। राजनीतिक दल इस मामले को लेकर अपने-अपने तरीके से जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और जांच एजेंसियों को क्या साक्ष्य मिलते हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद गंभीर साबित हो सकता है। वहीं यदि आरोप झूठे साबित होते हैं, तो यह राजनीतिक प्रतिशोध और कानूनी दुरुपयोग को लेकर नई बहस को जन्म देगा।

संपादकीय

नागरिकों संग शासन प्रशासन भी हो अनुशासित

खाड़ी युद्ध से उपजे हालात व बाधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बीच प्रधानमंत्री का ईंधन के उपयोग व सोने की खरीद में संयम बरतने का आह्वान निस्संदेह, वक्त की जरूरत है। लेकिन तेलंगाना के बाद बडोदरा से दूसरी बार उनके राष्ट्र को संबोधन व इसके समय को लेकर सवाल भी उठे हैं। निस्संदेह, हालात काफी दिनों से चुनौतीपूर्ण बने हैं, रुपये में तेज गिरावट व महंगे कच्चे तेल के आयात की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी दबाव में रहा है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि इस घोषणा के लिये विधानसभा चुनाव परिणामों का इंतजार क्यों किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता शीर्ष से किया गया आह्वान कई बार देश में असुरक्षाबोध पैदा करता है, जिसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। दरअसल, इससे कृत्रिम संकट पैदा करने वाले तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें दो राय नहीं कि देश बड़ी मात्रा में कच्चा तेल व सोना आयात करता है। जाहिर बात है जब इनकी वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो इन दोनों के कारण भारी दबाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। निस्संदेह, विषम वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना चुनौतियों से मुकाबले के लिये समझदारी भरे उपाय हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले डेढ़ माह में सरकार विधानसभा चुनावों में व्यस्त रही। इस दौरान आर्थिक प्रबंधन का मुद्दा हाशिये पर चला गया। अब इन चुनौतियों से मुकाबले के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों से विदेशों में शादियां टालने, सोना खरीदने से बचने के लिये कहना बताता है कि रुपये में तेज गिरावट से सरकार चिंतित है। कहा जा रहा है कि बार-बार अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा करने वाली सरकार को जनता से व्यवहार में संयम बरतने का आग्रह करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल, आशंका यह भी है कि इन कदमों के ऐसे भी नतीजे निकल सकते हैं,जिनकी उम्मीद न की गई हो। निर्विवाद रूप से सोना भारतीय संस्कारों में है। वहीं भारत में आभूषण उद्योग लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है। ऐसे में सोने की खरीद में गिरावट से संपन्न निवेशकों के मुकाबले श्रमिकों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर वर्क-फ्रॉम होम की नीति, काम करने वालों के बड़े तबके के लिए व्यावहारिक नहीं है। निस्संदेह, किसी भी आसन्न संकट में नागरिकों की जिम्मेदारी मायने रखती है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रियों के कारों के काफिलों पर भी अंकुश लगेगा.. क्या शासन प्रशासन की शाहखर्ची पर लगाम लगेगी...। यदि ऐसा नहीं होता तो जनता की स्वतःस्फूर्त पहल प्रभावित होगी। वैसे भी नागरिक जिम्मेदारी एक हद तक तो प्रभावी हो सकती है,लेकिन वह किसी आपातकालीन योजना का विकल्प नहीं हो सकती। सरकार को भी अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है। जहां तक सोने की खरीद पर संयम का सवाल है तो उससे देश में गहरा भावनात्मक लगाव जुड़ा रहा है। सोना हमारी संस्कृति, परंपरा, बचत और पारिवारिक समारोहों में गहरे तक शामिल रहा है। लेकिन सदियों से सम्मोहित करते सोने का आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा असर डालता है। ऐसे में राष्ट्र हितों के मद्देनजर जीवन यापन करना, राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने जैसा है। विगत में कई बार जब देश पर संकट आया तो लोगों ने राष्ट्र की संप्रुभता की रक्षा के लिये सोना तक दान किया। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल छह सौ से सात सौ टन सोना आयात होता है, लेकिन निर्यात का प्रतिशत ना के बराबर है। बताया जाता है कि देश का नब्बे फीसदी सोना आयात होता है। यह सोना अर्थव्यवस्था में सक्रिय न होकर घरों में एकत्र हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार देश के घरों में करीब 27 हजार टन सोना जमा है। बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करके आयात होने वाला सोना देश के चालू खाते और विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल असर डालता है। ऐसे में सोने पर संयम अर्थव्यवस्था को संबल देने में मददगार हो सकता है।

Gold नहीं खरीदने की मोदी की अपील के बाद ज्वैलर्स लाये नई योजना, पुराने सोने के बदले नये गहने खरीदने पर आकर्षक स्कीमें

"विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां निजी हाथों में सबसे अधिक सोना मौजूद है। यदि इस सोने को औपचारिक आर्थिक ढांचे में शामिल किया जाए तो हर वर्ष दो सौ से तीन सौ टन तक सोना आयात की जरूरत कम की जा सकती है।

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बढ़ते दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से एक वर्ष तक सोने की खरीद टालने की अपील के बाद अब इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। जहां सरकार विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को नियंत्रित करना चाहती है, वहीं देश का आभूषण उद्योग इस सुझाव को लेकर चिंता जता रहा है। उद्योग संगठनों का कहना है कि मांग को दबाने की बजाय देश में पहले से मौजूद निष्क्रिय सोने को आर्थिक व्यवस्था में शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने सरकार से सोना खरीद टालने की अपील के स्थान पर घरेलू सोना संग्रहण और पुनर्चक्रण व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। संगठन ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते आयात बिल को लेकर सरकार की चिंता उचित है, लेकिन व्यापक स्तर पर लोगों को सोना खरीदने से हतोत्साहित करने का असर पूरे आभूषण उद्योग पर पड़ सकता है।

इसे भी पढ़ें: सोना खरीदने से क्यों मना कर रहे हैं मोदी? क्या फिर से होने वाला है Work From Home? पेट्रोल-डीजल के दाम कबसे बढ़ेंगे?

फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा ने कहा कि समाधान मांग को खत्म करना नहीं, बल्कि देश में मौजूद निष्क्रिय सोने को व्यवस्थित तरीके से आर्थिक उपयोग में लाना है। उनके अनुसार घरेलू सोना संग्रहण, पुनर्चक्रण और उत्पादक उपयोग के जरिये विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उपभोक्ताओं की सोच अचानक नकारात्मक हुई तो दुकानों पर ग्राहकों की संख्या घटेगी, निर्माण आदेश कम होंगे और छोटे ज्वैलर्स तथा कारीगरों की आय पर गंभीर असर पड़ेगा।

फेडरेशन का कहना है कि यह केवल व्यापार का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा है। हम आपको बता दें कि भारत में लगभग साढ़े तीन करोड़ लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आभूषण उद्योग से जुड़े हुए हैं। देश के ग्रामीण और शहरी परिवारों में सोना केवल विलासिता की वस्तु नहीं माना जाता, बल्कि यह बचत, सामाजिक सुरक्षा और विवाह परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई परिवारों के लिए आभूषण पहनने योग्य बचत के रूप में काम करते हैं।

इसी कारण फेडरेशन ने सरकार को कई वैकल्पिक सुझाव दिए हैं। संगठन ने गिफ्ट आईएफएससी या इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज व्यवस्था के भीतर एक समर्पित बुलियन बैंक स्थापित करने की मांग की है। यह संस्था घरेलू सोने के संग्रहण, शुद्धिकरण, उधार व्यवस्था और निपटान का केंद्रीय मंच बन सकती है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ को अपने भौतिक सोना भंडार का बीस से तीस प्रतिशत तक नियामित ढांचे के तहत उधार देने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया गया है।

फेडरेशन ने वर्ष 2015 में शुरू की गई स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की समीक्षा की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि संरचनात्मक कमजोरियों के कारण यह योजना अपेक्षित स्तर तक सफल नहीं हो सकी। इसके साथ ही डीमैट स्वरूप वाले बुलियन जमा प्रमाणपत्र, सोना हस्तांतरण पर कर और जीएसटी तटस्थता तथा राष्ट्रीय स्तर पर सोना संग्रहण और आयात प्रतिस्थापन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने का सुझाव भी दिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां निजी हाथों में सबसे अधिक सोना मौजूद है। यदि इस सोने को औपचारिक आर्थिक ढांचे में शामिल किया जाए तो हर वर्ष दो सौ से तीन सौ टन तक सोना आयात की जरूरत कम की जा सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रोजगार पर नकारात्मक असर भी नहीं पड़ेगा।

देखा जाये तो भारत में सोने के आयात में लगातार बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में देश का सोना आयात चौबीस प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड इकहत्तर अरब अट्ठानवे करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इससे पिछले वर्ष यह अट्ठावन अरब डॉलर था। हालांकि मात्रा के हिसाब से आयात घटकर सात सौ इक्कीस टन रह गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेज उछाल के कारण आयात बिल तेजी से बढ़ा। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है और वैश्विक अनिश्चितता के दौर में लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के बढ़ते आयात से व्यापार घाटा और चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ता है।

इस बीच, मोदी सरकार ने सोने के आयात को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में आयात शुल्क बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत किया गया था, हालांकि बाद में आभूषण उद्योग को राहत देने और तस्करी रोकने के उद्देश्य से इसे घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौतों के कारण संयुक्त अरब अमीरात से सोने का आयात तेजी से बढ़ा है। आर्थिक शोध संस्था जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि दुबई के रास्ते तीसरे देशों का सोना कम शुल्क का लाभ लेकर भारत पहुंच रहा है, जिससे व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। संस्था ने सरकार से व्यापार समझौतों की समीक्षा, सख्त नियम लागू करने तथा भविष्य के समझौतों में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे उत्पादों को विशेष रियायतों से बाहर रखने की सिफारिश की है।

उधर, प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब सोना विनिमय योजनाएं भी चर्चा में आ गई हैं। लंबे समय से आभूषण दुकानों में पुराना सोना बदलकर नया आभूषण लेने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ताजा खरीद की तुलना में यह व्यवस्था अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय रही है। अब इसे एक वैकल्पिक उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

कई प्रमुख ज्वैलरी कंपनियां ग्राहकों को पुराना सोना बदलकर नया आभूषण लेने की सुविधा देती हैं। इस प्रक्रिया में पुराने आभूषण, टूटे हुए गहने, अनुपयोगी सोने की वस्तुएं और सोने के सिक्के तक स्वीकार किए जाते हैं। सबसे पहले प्रमाणित विधियों से सोने की शुद्धता जांची जाती है। इसके बाद उस दिन के बाजार भाव के अनुसार मूल्य तय किया जाता है और ग्राहक उसी राशि के आधार पर नया आभूषण खरीद सकता है। हालांकि ग्राहक को नए आभूषण पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी तथा पत्थर या अशुद्धि होने पर कटौती का भुगतान करना पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी ग्राहक के पास बीस ग्राम का बाइस कैरेट पुराना आभूषण है और उस दिन सोने का भाव तेरह हजार नौ सौ पैंतालीस रुपये प्रति ग्राम है, तो उसके सोने का अनुमानित मूल्य लगभग दो लाख अठहत्तर हजार नौ सौ रुपये होगा। इस राशि का उपयोग नया आभूषण खरीदने में किया जा सकता है।

बहरहाल, सरकार और उद्योग के बीच अब इस बात पर सहमति बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है कि विदेशी मुद्रा बचत और रोजगार सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उद्योग संगठनों का मानना है कि यदि घरेलू सोने को व्यवस्थित रूप से आर्थिक प्रवाह में लाया जाए तो देश को आयात पर निर्भरता घटाने के साथ रोजगार और कारोबार दोनों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

प्रेरणा

विश्वास की शक्ति से विजय

मनुष्य का जीवन संघर्षों, चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए साहस, परिश्रम और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास वह अदृश्य शक्ति है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने का हौसला देती है। जिस इंसान को अपनी क्षमता पर भरोसा होता है, वह असंभव दिखाई देने वाले कार्यों को भी संभव बना देता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है, वह छोटे अवसरों को भी खो देता है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों ने हमेशा आत्मविश्वास को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया है।

एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा। वह बेहद चिंतित और निराश दिखाई दे रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, "स्वामीजी, मेरे भीतर हमेशा डर बना रहता है। मैं कुछ नया करने से घबराता हूं। जब भी कोई बड़ा कार्य शुरू करने का सोचता हूं, मन में असफलता का भय पैदा हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए शुरुआत करने का साहस ही नहीं कर पाता।" युवक की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद शांत भाव से मुस्कुराए और उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए।

नदी का बहाव उस समय काफी तेज था। किनारे पर कई लोग खड़े थे, लेकिन वे नाव में बैठने से डर रहे थे। कोई कह रहा था कि पानी बहुत गहरा है, तो कोई डूबने के भय से पीछे हट रहा था। तभी वहां एक वृद्ध मल्लाह आया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ नाव संभाली और बिना किसी घबराहट के नदी पार करने लगा। उसकी आंखों में स्थिरता और चेहरे पर विश्वास झलक रहा था। कुछ ही देर में वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया।

स्वामी विवेकानंद ने युवक से पूछा, "तुम्हें क्या लगता है, इस वृद्ध मल्लाह और इन भयभीत लोगों में क्या अंतर है?" युवक ने उत्तर दिया, "स्वामीजी, उस मल्लाह को अपने अनुभव और कौशल पर विश्वास है, इसलिए वह नहीं डरा।" विवेकानंद ने कहा, "यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जब तक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तब तक छोटी-सी चुनौती भी उसे बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, कठिनाइयां छोटी प्रतीत होने लगती हैं।"

उन्होंने युवक को समझाया कि भय जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे कभी डर महसूस न हुआ हो। लेकिन साहसी वही कहलाता है, जो भय के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। यदि कोई व्यक्ति केवल डर के कारण प्रयास करना छोड़ दे, तो वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, जो असफलता की संभावना के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ते।

आज के समय में अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार के भय से जूझ रहे हैं। विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने से डरते हैं। युवा अपने सपनों का पीछा करने से घबराते हैं। कई लोग व्यापार शुरू करने का साहस नहीं जुटा पाते क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान का डर होता है। कुछ लोग मंच पर बोलने से डरते हैं, तो कुछ समाज की आलोचना के भय से अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते। इन सभी भय का मूल कारण आत्मविश्वास की कमी है। जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानने लगता है, तब उसका मन हर परिस्थिति में नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है।

आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और अनुभव से विकसित होने वाली शक्ति है। जब व्यक्ति छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू करता है, तब धीरे-धीरे उसका आत्मबल बढ़ने लगता है। जैसे एक बच्चा कई बार गिरने के बाद चलना सीखता है, वैसे ही मनुष्य भी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है। यदि वह हर असफलता के बाद हार मान ले, तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखे, तो एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है।

स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं को यह संदेश देते थे कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। वे कहते थे कि मनुष्य स्वयं अपनी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यदि वह हर समय अपनी कमियों के बारे में सोचता रहेगा, तो उसका आत्मबल कमजोर होता जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी योग्यताओं और संभावनाओं पर ध्यान देगा, तो उसके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। आत्मविश्वास व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदल देता है। वही परिस्थितियां, जो पहले कठिन लगती थीं, अब अवसरों के रूप में दिखाई देने लगती हैं।

जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वे कठिनाइयों से घबराते नहीं। वे जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें कुछ नया सिखाने आई है। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, तो उसे हार का भय हो सकता है, लेकिन यदि वह डर के कारण खेलने से ही मना कर दे, तो कभी जीत नहीं पाएगा। उसी प्रकार जीवन में भी जोखिम उठाना आवश्यक है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती।

आत्मविश्वास केवल कार्यक्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जो इंसान स्वयं पर विश्वास करता है, वह दूसरों की आलोचनाओं से जल्दी टूटता नहीं। वह अपनी गलतियों से सीखता है और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ते। उनके भीतर यह विश्वास होता है कि यदि वे प्रयास करते रहेंगे, तो एक दिन अवश्य सफल होंगे।

स्वामी विवेकानंद का जीवन इसी आत्मविश्वास का प्रतीक था। उन्होंने युवाओं को हमेशा निर्भीक बनने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि भय मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है, जबकि आत्मविश्वास उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने मन से यह सोच निकाल दे कि वह कमजोर है, तो उसके भीतर असीम शक्ति जागृत हो सकती है। संसार की सबसे बड़ी विजय वही है, जो मनुष्य अपने भय पर प्राप्त करता है।

इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। डर और संकोच को अपने सपनों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भय का सामना करना सीख लेता है, उसके लिए सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। आत्मविश्वास वह दीपक है, जो अंधकार भरे मार्ग को भी रोशन कर देता है। जब मनुष्य यह विश्वास कर लेता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। यही आत्मविश्वास जीवन को नई दिशा देता है और साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है।

वैश्विक संकट के दौर में दूरगामी सोच का परिणाम है प्रधानमंत्री की अपील

ऐसा नहीं है कि भारत विदेशी मुद्रा के मामलें में संकट में हो बल्कि वास्तविकता तो यह है कि 10 अप्रेल, 2026 के आंकड़ों की ही बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार आज उच्चतम स्तर पर है। 700 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का विदेशी मुद्रा भण्डार भारत के पास है। एक मोटे अनमुन के अनुसार आगामी 11 माह से अधिक समय तक आयात मांग की पूर्ति इस राशि से आसानी से हो सकती है। विदेशी मुद्रा भण्डार से एफसीए यानी कि विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भण्डार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर इसके सबके बावजूद भविष्य के संभावित संकट के हालातों से निपटने की आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाती है तो यही दूरदृष्टि कहलाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भविष्य के वैश्विक हालात साफ दिखाई दे रहे हैं। हालातों में सुधार की संभावना निकट भविष्य में दिखाई भी नहीं दे रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल एक वर्ष के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती का आग्रह देशवासियों से किया है। इसमें ईंधन बचाना, सोना नहीं खरीदने, विदेशी यात्राओं व विदेशों में शादी नहीं करने, खाने के तेल के उपयोग में 10 प्रतिशत तक की कटौती व खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक की कटौती करने का सुझाव प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशवासियों से आग्रह को लेकर आलोचक भले ही मुद्दा बनाने का प्रयास करें पर वैश्विक हालात आज सबके सामने हैं। देशवासियों को मालूम है कि पेट्रोलियम उत्पादों इनमें कच्चे तेल से लेकर गैस आदि आदि शामिल है आदि के लिए आयात पर निर्भरता अधिक है। देश में 979 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना आयात होता है जिसमें से करीब 38 प्रतिशत आयात केवल और केवल पेट्रोलियम पदार्थों पर ही हो रहा है। सोना-चांदी और इलेक्ट्रोनिक्स के साथ ही फर्टिलाइजरों के मामलें में भी विदेशों पर निर्भरता अधिक है। करीब 10 प्रतिशत राशि सोने के आयात पर खर्च होती है। यदि समग्र रुप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के सिकन्दराबाद से देशवासियों से जो आग्रह किया है वह ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह से देशवासियों के लिए दुबिधाजनक हो। वैश्विक संकट के चलते देश-दुनिया की इकोनोमी पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देशवासियों से दूरदृष्टियुक्त अपील से कोरोना काल की याद ताजा हो रही है तो पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री की तत्कालीन अन्न संकट के दौरान सप्ताह में एक दिन के उपवास के आग्रह की और चला जाता है। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध सीज़फायर के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दूसरी और दोनों ही देशों की हठधर्मिता के कारण हार्मुज जलडमरुमध्य से परिवहन बाधित होने का परिणाम दुनिया के देशों के सामने हैं। दुनिया के देशों को यह समझ लेना होगा कि अमेरिका-ईरान युद्ध केवल दो या तीन देशों के बीच युद्ध तक सीमित ना होकर इसके असर से आज कोई देश दूर दूर तक अछूता नहीं दिखाई दे रहा है। यह दो देशों की अहम् की लड़ाई ना होकर समूची मानवता को प्रभावित करने वाले हालात है। आज दुनिया के देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। बिना किसी अन्य देश के सहयोग के कोई भी देश अपने स्तर पर अपने देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक उदारीकरण के बाद से आज विश्व विश्व ग्राम में परिवर्तित हो गया है। एक बात यह भी साफ हो जानी चाहिए कि आज अमेरिका-इजरायल और ईरान संकट का हल निकल भी आता है तब भी वैश्विक हालात सामान्य होने में लंबा समय लग जाएगा। युद्धरत देश यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि उनके अहम् के चलते दुनिया आज सालों पीछे जा रही है। विकास बाधित हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं।

आज सबको मालूम है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात प्रभावित हो रहा है। हार्मुज का रास्ता अवरुद्ध है। हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि ईरान को प्रतिदिन 2800 करोड़ रुपए के कच्चे तेल को समुद्र में बहाना पड़ रहा है। तेल उत्पादक अन्य देश भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने, सार्वजनिक परिवहन वाहनों के उपयोग और वाहन पूलिंग का एक साल का सुझाव या आग्रह दूरदृष्टिपूर्ण व देशहित में ही माना जाना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का बढ़ावा देना भविष्य के पर्यावरण संकट से बचाव और हरित उर्जा को बढ़ावा देने में ही सहायक हो सकेगा। इसी तरह से हमारे देश में सोने के खरीद के प्रति खास मोह रहता आया है पर हालातों को देखते हुए व्यापक राष्ट्रहित में एक साल के लिए सोना नहीं खरीदे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से केवल शानों शोकत के लिए विदेशी यात्राएं करने से बचने की सलाह और विदेशों में शादी करने के स्थान पर स्थानीय पर्यटन और देश में ही एक से एक बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशंस पर शादी करने से जहां खर्च कम होगा, देश के डेस्टिनेशनों की वैश्विक पहचान के साथ ही विदेशी पूंजी भी बचेगी। इसी तरह से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खेती और खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने से आज देश दो चार हो रहा है। जैविक खाद और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने का आग्रह निश्चित रुप से सकारात्मक ही है। जहां तक मीटिंग्स का प्रश्न है कोविड़ के बाद से सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर अधिकांष मीटिंग्स अब हाईब्रीड मोड पर ही होने लगी है। वर्कफ्राम होम को अवश्य प्रोत्साहित किया जा सकता है।

लब्बो-लबाब यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो देशवासियों से आग्रह किया है उनमें से एक भी ऐसा आग्रह नहीं है जिससे हमारे दैनिक जीवन चर्या प्रभावित हो रही हो। एक भी ऐसा बिन्दु नहीं है जिससे आमजन प्रभावित हो रहा हो। सीधे सीधे एक साल के लिए अपनी आदत व आवश्यकताओं में जरुरी बदलाव के लिए कहा जा रहा है ताकि वैश्विक संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था व देश के आमलोगों को प्रभावित ही ना कर सकें। एक साल सोना नहीं खरीदने या ईवी वाहन या सार्वजनिक वाहन का उपयोग या विदेशों में शादी आदि कार्यक्रम आयोजित ना करने या विदेश घूमने नहीं जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।

अभियान

आस्था की उड़ान को तकनीक का सहारा

उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक भी हैं। हर वर्ष देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्गों को पार करके इन धामों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि पहले यह यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती थी, क्योंकि दुर्गम रास्ते, बदलता मौसम और लंबी पैदल दूरी यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनते थे। लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीक और बेहतर व्यवस्थाओं ने इस यात्रा को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। इन्हीं आधुनिक प्रयासों में हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरी है।

इस वर्ष चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड नागर विमानन विकास प्राधिकरण यानी यूसीएडीए द्वारा संचालित आधुनिक हेलीकॉप्टर सेवाओं ने यात्रा को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बना दिया है। 22 अप्रैल से अब तक 21 हजार से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठा चुके हैं। यह आंकड़ा केवल सुविधा का नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के बढ़ते विश्वास और आधुनिक व्यवस्था की सफलता का भी प्रमाण है।

फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी जैसे प्रमुख स्थानों से संचालित शटल सेवाओं के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के दर्शन कराए गए हैं। इन सेवाओं ने विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बना दिया है। पहले जहां कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई श्रद्धालुओं को थका देती थी, वहीं अब कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से धाम तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा चार्टर्ड सेवाओं के माध्यम से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक परिवहन व्यवस्था अब धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

चारधाम यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती हमेशा मौसम को लेकर रहती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम पल-पल बदलता है। अचानक बारिश, तेज हवाएं और घना कोहरा हेलीकॉप्टर संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण एवं संचार केंद्र यानी ICCCC की स्थापना की गई है। यह आधुनिक केंद्र खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर सेवाओं की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए रखता है।

इस केंद्र में नागर विमानन महानिदेशालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग और यूसीएडीए की संयुक्त टीम चौबीसों घंटे कार्य कर रही है। हवाई यातायात नियंत्रण के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक उड़ान की निगरानी की जा रही है। आधुनिक पीटीजेड कैमरों के माध्यम से हेलीकॉप्टरों के आगमन और प्रस्थान पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। यह तकनीकी व्यवस्था केवल सुविधा नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता को भी दर्शाती है।

उत्तराखंड सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि चारधाम यात्रा को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार यात्रा को सुरक्षित, सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। यूसीएडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुसार प्रत्येक हेलीकॉप्टर उड़ान की सक्रिय निगरानी की जा रही है तथा मौसम और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही उड़ानों को अनुमति दी जा रही है। इससे यात्रियों को न केवल सुरक्षित यात्रा मिल रही है, बल्कि उनका विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा आधार है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार से पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिली है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक सेवाओं के पहुंचने से विकास की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं।

हालांकि हेलीकॉप्टर सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता के साथ कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। मौसम की अनिश्चितता, सीमित उड़ान क्षमता और बढ़ती मांग के कारण यात्रियों को कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। डिजिटल बुकिंग, ऑनलाइन निगरानी और तकनीकी समन्वय ने यात्रियों की समस्याओं को काफी हद तक कम किया है। आने वाले समय में इन सेवाओं को और अधिक उन्नत बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है।

चारधाम यात्रा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमालय की गोद में स्थित ये धाम श्रद्धालुओं को केवल धार्मिक संतोष ही नहीं देते, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव कराते हैं। जब श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्गों को पार करके मंदिरों तक पहुंचते हैं, तो उनके भीतर एक विशेष प्रकार की श्रद्धा और आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। अब हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से यह अनुभव अधिक लोगों तक पहुंच रहा है, विशेषकर उन लोगों तक जो स्वास्थ्य या उम्र के कारण कठिन यात्रा नहीं कर पाते थे।

इस वर्ष यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हुई थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। इसके बाद केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हेलीकॉप्टर सेवाएं इस बढ़ती भीड़ को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

आधुनिक तकनीक और धार्मिक आस्था का यह संगम आज चारधाम यात्रा की नई पहचान बन चुका है। जहां एक ओर श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ धामों के दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीकी व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल यात्रा को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ मिलकर कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और विश्वस्तरीय रूप में सामने आएगी, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए आस्था की उड़ान बनकर निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : RAGINI JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

बदलते मौसम का डबल अटैक, कहीं लू तो कहीं आंधी-ओलावृष्टि ने बढ़ाई मुश्किलें

देशभर में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। एक ओर कई राज्यों में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी ओर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत तक मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पहाड़ी राज्यों में तेज तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं ने तबाही मचाई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत के साथ नई परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं।

राष्ट्रीय राजधानी New Delhi में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों को गर्मी से कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन अचानक मौसम बदलने से यातायात और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका भी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। Punjab और Haryana में 12 से 15 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी Uttar Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand और Himachal Pradesh में भी तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। सोमवार को आए तेज तूफान और बारिश ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में घालिंचा, घरयाल, कामेडा और कंडी गांवों में कई मकानों और गौशालाओं की छतें उड़ गईं। तेज हवाओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। मंडी जिले के सुंदरनगर में पेड़ गिरने से कई

वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई।

राज्य के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। शिमला, कांगड़ा और बैजनाथ क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए और बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। जलोरी दर्रे पर पेड़ गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी।

इस बीच कांगड़ा जिले के वृंदावन क्षेत्र से एक दुखद घटना भी सामने आई, जहां बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के एक लाइनमैन की मौत हो गई। लगातार खराब मौसम के बीच राहत और मरम्मत कार्य में जुटे कर्मचारियों के सामने भी बड़ा जोखिम बना हुआ है।

मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि, गरज-चमक और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक मौसम बदलने से भूस्खलन और सड़क बाधित होने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं।

पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। Assam और Meghalaya में लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं Nagaland, Manipur, Mizoram और Tripura में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में पहले से ही नमी और बादलों का असर बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को उमस और बारिश दोनों का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्वी भारत में भी मौसम का असर दिखाई देगा। Bihar में 12 से 14 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। Jharkhand में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा West Bengal, Odisha और Sikkim में भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 17 मई तक बारिश का प्रभाव बना रह सकता है।

मौसम विभाग का कहना है कि 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके कारण उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम और अधिक खराब हो सकता है। यदि यह सिस्टम मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय देश में मौसम का यह असामान्य व्यवहार जलवायु परिवर्तन और बदलते वैश्विक मौसमी पैटर्न का संकेत भी हो सकता है। एक ही समय में कहीं भीषण गर्मी और कहीं तेज बारिश की स्थिति यह दर्शाती है कि मौसम चक्र पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित और चरम होता जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वालों, किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आने वाले कुछ दिन उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर मंडलीय रेलवे अस्पताल, साबरमती में रक्तदान शिविर का आयोजन

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दिनांक 12 मई 2026 को मंडलीय रेलवे अस्पताल, साबरमती में सर्वोदय ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. भानुमति शेखर, सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (प्रशासन) तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ नर्सिंग स्टाफ द्वारा दीप प्रज्वलन एवं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया।

रक्तदान शिविर को अस्पताल कर्मचारियों एवं रक्तदाताओं से उत्साहपूर्ण प्रतिसाद प्राप्त हुआ। शिविर के दौरान कुल 43 यूनिट रक्त सफलतापूर्वक एकत्रित किया गया।

समारोह के दौरान शीघ्र सेवानिवृत्त होने जा रही श्रीमती मिनाक्षी परमार एवं श्रीमती शर्मिष्ठा को अस्पताल में उनकी समर्पित सेवाओं एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए "बेस्ट नर्स" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस समारोह में मंडलीय रेलवे अस्पताल, साबरमती के सभी नर्सिंग कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया।

पुरस्कारों का वितरण सहायक नर्सिंग अधिकारी श्रीमती जेबा रहमान शेख द्वारा किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम नर्सिंग स्टाफ के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान, टीम भावना एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

अशोक खरात मामले में रूपाली चाकणकर से 7 घंटे तक पूछताछ, एसआईटी ने वित्तीय संबंधों की जांच तेज की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। नासिक के भोंडुबाबा अशोक खरात का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। पुलिस ने आरोपी अशोक खरात की विभिन्न मामलों में हिरासत बढ़ा दी है। कल राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चकांकर से भी एसआईटी ने पूछताछ की। उनसे कुल 7 घंटे पूछताछ की गई। इसमें से एसआईटी प्रमुख तेजस्वी सतपुत ने दो घंटे पूछताछ की।

अन्य राजनीतिक समूह किसके कहने पर अशोक खरात के मंदिर में आ रहे थे? रूपाली चाकंकर के अशोक खरात से संबंधित वित्तीय लेनदेन किन बैंक खातों में किए गए थे, इसकी भी जांच की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, एसआईटी अधिकारियों ने रूपाली चाकंकर से कई सवाल पूछे। आपका अशोक खरात से कब से संबंध था? क्या शिवनिका संगठन में रहते हुए आपको अशोक खरात के इन सभी मामलों की जानकारी थी? क्या अशोक खरात के साथ की गई पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान विधिवत थे? क्या पूजा-अर्चना का अशोक खरात से कोई वित्तीय संबंध था? अशोक खरात के साथ ली गई तस्वीरें और वीडियो कब के हैं? वे किस कार्यक्रम के हैं? शिवनिका संगठन की बैठकों में क्या काम होता है? एसआईटी ने ये सवाल रूपाली चाकंकर से पूछे।

अंजलि दमानिया ने जांच की मांग की

सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने जांच की मांग करते हुए कहा, "कहा जा रहा है कि रूपाली चाकंकर ने एसआईटी जांच के लिए जाते समय रास्ते में अपनी गाड़ी बदल ली। साथ ही, पुणे से नासिक जाते समय रूपाली चाकंकर ने अपनी गाड़ी तीन-चार बार रोकी। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए।"

जहरीले रसायनों से युक्त फलों और सब्जियों से स्वास्थ्य को खतरा, मुंबई में तरबूज खाने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा)

आज देश में लगभग हर खाद्य और पेय पदार्थ में मिलावट पाई जाती है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जीवन रक्षक दवाइयां भी मिलावट से मुक्त नहीं हैं। दूध से लेकर पानी तक, गेहूं से लेकर मिर्च और मसालों तक, फलों से लेकर सब्जियों तक, हर चीज में मिलावट है या अत्यंत हानिकारक रसायनों का मिश्रण है।

अच्छे स्वास्थ्य और सेहत बनाए रखने के लिए फल और हरी सब्जियों का सेवन आवश्यक माना जाता है। डॉक्टर भी इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह देते हैं। हालांकि, इन फलों और सब्जियों की खेती में जहरीले रसायनों का बढ़ता उपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। फलों को समय से पहले पकाने, उनकी चमक बढ़ाने, बासी सब्जियों को ताजा करने और हरी सब्जियों की वृद्धि को तेज करने के लिए कई प्रकार के जहरीले रसायनों का उपयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

मुंबई के पायधुनी इलाके में भी हाल ही में ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों की तरबूज खाने से मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों के आंतरिक अंगों और तरबूज के नमूनों में चूहे मारने वाले जहर के अंश पाए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जहर तरबूज के अंदर कैसे पहुंचा। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि तरबूज को पकाने के लिए विशेष रूप से जहर का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

इस मामले में पुलिस की चल रही जांच के बीच, अब एक अहम सवाल उठता है कि इन चार परिवार के सदस्यों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? सीधे शब्दों में कहें तो, कीटनाशक मूल रूप से फसलों को कीटों और अन्य जानवरों से बचाने के लिए विकसित किए गए थे। लेकिन इनका अंधाधुंध और अवैज्ञानिक उपयोग अब मानव स्वास्थ्य और जीवन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इस संदर्भ में, यह समय की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से फलों और सब्जियों का निरीक्षण करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

सोना वायदा में 116 रुपये की वृद्धिः चांदी वायदा में 2112 रुपये की नरमीः क्रूड ऑयल वायदा 326 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 272577.52 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 45378.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 227199.05 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3672.26 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 32151.59 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 153999 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 154243 रुपये और नीचे में 153016 रुपये पर पहुंचकर, 153663 रुपये के पिछले बंद के सामने 116 रुपये या 0.08 फीसदी बढ़कर 153779 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 26 रुपये या 0.02 फीसदी की मजबूती के साथ 123300 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 7 रुपये या 0.05 फीसदी की मजबूती के साथ 15453 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 153575 रुपये के भाव पर खूलकर, 153990 रुपये के दिन के उच्च और 152758 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 7 रुपये या 0 फीसदी की मजबूती के साथ 153452 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 153655 रुपये के भाव पर खूलकर, 154200 रुपये के दिन के उच्च और 153025 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153656 रुपये के पिछले बंद के सामने 94 रुपये या 0.06 फीसदी की मजबूती के साथ 153750 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 280229 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 282755 रुपये और नीचे में 273126 रुपये पर पहुंचकर, 278311 रुपये के पिछले बंद के सामने 2112 रुपये या 0.76 फीसदी औंधकर 276199 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 1390 रुपये या 0.5 फीसदी की गिरावट के साथ 278293 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 1373 रुपये या 0.49 फीसदी लुढ़ककर 278325 रुपये प्रति किलो बोला गया।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 45378.48 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 227199.05 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 32151.59 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

मेटल वर्ग में 7334.70 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 9.35 रुपये या 0.68 फीसदी बढ़कर 1378.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 3.55 रुपये या 1 फीसदी बढ़कर 359.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 1.8 रुपये या 0.48 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 377.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 40 पैसे या 0.2 फीसदी के सुधार के साथ 203.4 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5774.43 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9457 रुपये के भाव पर खूलकर, 9765 रुपये के दिन के उच्च और 9419 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 326 रुपये या 3.48 फीसदी की बढ़त के साथ 9702 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 326 रुपये या 3.48 फीसदी की मजबूती के साथ 9703 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 279.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 281.7 रुपये के दिन के उच्च और 276.6 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 50 पैसे या 0.18 फीसदी टूटकर 277.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 60 पैसे या 0.22 फीसदी की नरमी के साथ 277 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 993.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.1 रुपये या 0.21 फीसदी की तेजी के संग 1020 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11742.15 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20409.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 6191.58 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 557.01 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 20.00 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 552.37 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4019.70 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1728.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 10.40 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11659 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 66971 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26800 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 362846 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 53109 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8091 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22425 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 75284 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19449 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31124 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 39.8 रुपये की बढ़त के साथ 121.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 25 पैसे की नरमी के साथ 9.45 रुपये हुआ।

सोना मई 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 61 रुपये की बढ़त के साथ 362 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 116.5 रुपये की बढ़त के साथ 831.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 91 पैसे के सुधार के साथ 5.08 रुपये हुआ। जस्ता मई 405 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.24 रुपये की बढ़त के साथ 2.25 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 194.3 रुपये की गिरावट के साथ 148.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 10 पैसे की नरमी के साथ 12.15 रुपये हुआ।

सोना मई 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 14.5 रुपये की बढ़त के साथ 270 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 565.5 रुपये की बढ़त के साथ 4732.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.64 रुपये की गिरावट के साथ 4.86 रुपये हुआ। जस्ता मई 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5 पैसे के सुधार के साथ 1.1 रुपये हुआ।

सरकारी बैंकों की ऐतिहासिक छलांग, चौथे साल भी रिकॉर्ड मुनाफे से बदली तस्वीर

एक समय था जब देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बढ़ते एनपीए, घाटे, खराब ऋण और कमजोर बैलेंस शीट की वजह से लगातार आलोचनाओं के केंद्र में रहते थे। सरकारी बैंकों की हालत को लेकर यह धारणा बन गई थी कि वे केवल सरकारी सहारे पर टिके हुए संस्थान हैं, जिनकी कार्यक्षमता निजी बैंकों के मुकाबले कमजोर होती जा रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब वही सरकारी बैंक रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं, ऋण वितरण बढ़ा रहे हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका को नए आत्मविश्वास के साथ निभा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों ने इस बदलाव को और मजबूत कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष 1.98 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो लगातार चौथा साल है जब सरकारी बैंकों का मुनाफा नए शिखर पर पहुंचा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल परिचालन लाभ बढ़कर 3.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह केवल एक वित्तीय उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आए व्यापक सुधारों का संकेत है। सरकारी बैंकों के बेहतर प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी बैलेंस शीट का मजबूत होना, खराब ऋणों में कमी, बेहतर जोखिम प्रबंधन और बढ़ती ऋण मांग को माना जा रहा है।

देश के सभी सरकारी बैंकों का समेकित कारोबार भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। 31 मार्च 2026 तक उनका कुल कारोबार बढ़कर 283.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। जमा राशि और ऋण वितरण दोनों मोर्चों पर बैंकों ने मजबूत प्रदर्शन किया है। बैंकों की कुल जमा राशि 10.6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 156.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। विशेषज्ञ इसे आम लोगों और संस्थागत निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत मान रहे हैं।

दरअसल, बैंकिंग क्षेत्र में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। जब जमाकर्ता किसी बैंक में अपना पैसा सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी बैंक दीर्घकालिक रूप से मजबूत बन पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंकों ने तकनीकी सुधार, डिजिटल बैंकिंग विस्तार और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है।

ऋण वितरण के मोर्चे पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मजबूत बढ़त दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ऋण वितरण 15.7 प्रतिशत बढ़कर 127 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह आंकड़ा केवल बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती नहीं दिखाता, बल्कि यह भी संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था में निवेश और कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और खुदरा ऋण क्षेत्रों में बढ़ती मांग ने बैंकों की ऋण पुस्तिका को विस्तार दिया है।

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बेहतर प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। मंत्रालय के अनुसार सरकारी बैंक अब अधिक लचीले, स्थिर और संस्थागत रूप से मजबूत हो चुके हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों का परिणाम है।

एक समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती एनपीए यानी खराब ऋण थे। बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट, फंसे हुए कर्ज और कमजोर वसूली प्रणाली ने इन बैंकों की हालत खराब कर दी थी। लेकिन अब स्थिति में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकारी बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.93 प्रतिशत पर आ गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति मानी जा रही है।

एनपीए में कमी का मतलब यह है कि अब बैंकों के फंसे हुए ऋण कम हो रहे हैं और उनकी वसूली क्षमता बेहतर हुई है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई, ऋण निगरानी प्रणाली में सुधार और जोखिम प्रबंधन के नए उपायों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके साथ ही बैंकों ने अपने प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को भी मजबूत बनाए रखा है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 90 प्रतिशत से अधिक का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बनाए रखने में सफल रहे हैं।

वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक मजबूती का दावा, आत्मनिर्भरता पर सरकार का बड़ा भरोसा

दुनिया इस समय गहरे आर्थिक और भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, वैश्विक व्यापार युद्ध, महंगाई का दबाव, बदलते शुल्क ढांचे और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की धीमी रफ्तार ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव झेल रही हैं। ऐसे माहौल में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या देश इस वैश्विक संकट के बीच अपनी विकास गति बनाए रख पाएगा। इसी बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने यह भरोसा जताया है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इसका आधार देश की मजबूत आर्थिक संरचना तथा भारत में बढ़ता वैश्विक विश्वास है।

नई दिल्ली में आयोजित Confederation of Indian Industry के वार्षिक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कठिन जरूर हैं, लेकिन भारत ने हर संकट को अवसर में बदलने की क्षमता दिखाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, बढ़ती महंगाई, व्यापारिक शुल्कों में बदलाव और सप्लाई चेन संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिरता और लचीलापन बनाए रखा है। उनके अनुसार भारत की आर्थिक ताकत केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी संस्थागत क्षमता, मजबूत घरेलू बाजार और दूरदर्शी नीतियों में भी दिखाई देती है।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इसकी विकास गति को मजबूत घरेलू मांग का बड़ा सहारा मिला है। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं निर्यात और बाहरी मांग पर अत्यधिक निर्भर हैं, जबकि भारत का घरेलू बाजार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश की विशाल आबादी, बढ़ती आय, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार उपभोग को लगातार मजबूती दे रहा है। यही वजह है कि वैश्विक मांग में सुस्ती के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है।

उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के पास इस समय इतना मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है कि वह 11 महीने से अधिक के आयात को कवर कर सकता है। यह किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार केवल मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच भरोसा भी बढ़ाता है। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के समय यही भंडार किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करता है।

गोयल ने यह भी कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं, औद्योगिक सुधारों और निवेश अनुकूल नीतियों के जरिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भरता केवल आयात कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में रणनीतिक कदम है।

निर्यात प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष लगभग 863 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च निर्यात आंकड़े को छूने की तैयारी में है। यदि यह लक्ष्य हासिल होता है, तो यह भारत की वैश्विक व्यापार क्षमता का ऐतिहासिक प्रमाण होगा। सेवा क्षेत्र विशेष रूप से आईटी, वित्तीय सेवाएं, फार्मा और इंजीनियरिंग उत्पादों ने निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का बढ़ता निर्यात इस बात का संकेत है कि वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने व्यापार घाटे को लेकर भी सकारात्मक तस्वीर पेश की। उनके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं में भारत का कुल व्यापार घाटा देश को मिलने वाले वार्षिक प्रेषण यानी विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि से काफी कम है।

ममता का अंत या मजबूरी की चीख? धौलपुर में मां ने मासूम संग तालाब में कूदकर दी जान

Dholpur जिले से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मां और बच्चे के रिश्ते को दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन जब वही मां अपनी दो साल की मासूम बच्ची को तालाब में फेंकने के बाद खुद भी पानी में कूद जाए, तो यह केवल एक आत्महत्या की घटना नहीं रह जाती, बल्कि समाज, परिवार और मानसिक परिस्थितियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है। धौलपुर के मनियां थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। गांव के लोगों की आंखों के सामने कुछ ही मिनटों में एक परिवार उजड़ गया और तालाब का शांत पानी मातम में बदल गया।

घटना मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे बने एक तालाब में मंगलवार को एक महिला और उसकी मासूम बच्ची के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआत में ग्रामीणों को केवल महिला का शव दिखाई दिया था, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ तालाब के पास देखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने दोबारा रेस्क्यू अभियान चलाया और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची का शव भी पानी से बाहर निकाला गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार घटना बेहद तेजी से हुई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 27 वर्षीय महिला अपनी दो साल की बच्ची को लेकर तालाब के आसपास घूम रही थी। शुरुआत में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला कुछ देर तक तालाब किनारे खड़ी रही और फिर अचानक उसने बच्ची को तालाब में फेंक दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते या उसे रोकने के लिए दौड़ते, महिला खुद भी तालाब में कूद गई।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई ग्रामीण तालाब की ओर दौड़े और महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला गया। जब लोगों ने बताया कि महिला के साथ एक बच्ची भी थी, तब पुलिस ने तत्काल दोबारा तलाशी अभियान शुरू कराया। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची का शव भी बरामद कर लिया गया।

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान सुमन पत्नी जितेंद्र लोधा निवासी कुइयां गांव बसेड़ी के रूप में हुई है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनकी वजह से महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ इतना खौफनाक कदम उठा लिया।

मनियां थाना प्रभारी नीरज शर्मा के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस महिला के पारिवारिक और सामाजिक हालात की जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला किसी मानसिक तनाव, घरेलू विवाद, आर्थिक परेशानी या अन्य किसी दबाव से गुजर रही थी या नहीं।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि समाज में मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव किस हद तक लोगों को तोड़ रहे हैं। अक्सर ऐसे मामलों में महिलाएं लंबे समय तक मानसिक पीड़ा झेलती रहती हैं, लेकिन उनकी स्थिति को समझने वाला कोई नहीं होता। कई बार घरेलू विवाद, आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव या सामाजिक दबाव इंसान को अंदर से इतना कमजोर कर देते हैं कि उसे जीवन खत्म करना ही अंतिम रास्ता नजर आने लगता है।

सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस त्रासदी में एक मासूम बच्ची की भी जान चली गई, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं था। गांव में घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। लोगों के बीच यही चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक मां को अपनी बच्ची समेत मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मोबाइल कॉल डिटेल, पारिवारिक संबंध और महिला की हाल की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है।

धौलपुर की यह घटना केवल एक आत्महत्या की खबर नहीं है, बल्कि यह उस बढ़ते मानसिक और सामाजिक दबाव की तस्वीर भी है, जो कई परिवारों को भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी और भावनात्मक सहयोग के अभाव के कारण कई लोग चुपचाप तनाव में जीते रहते हैं। जब समस्याएं असहनीय हो जाती हैं, तब कई बार ऐसे भयावह कदम सामने आते हैं।

फिलहाल पूरे इलाके में इस दर्दनाक घटना को लेकर शोक और स्तब्धता का माहौल है। तालाब किनारे जहां कुछ घंटे पहले सामान्य हलचल थी, वहां अब केवल सन्नाटा और लोगों की नम आंखें दिखाई दे रही हैं।

अहमदाबाद मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अंतिम मील कनेक्टिविटी को मिल रही नई गति

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा को और अधिक सशक्त बनाने तथा निर्बाध फर्स्ट एवं लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रैपिडो एवं उबर के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से एकीकृत मोबिलिटी सेवाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

इस पहल के अंतर्गत साबरमती रेलवे स्टेशन पर देश का पहला "Rapido Traveler's Lounge" स्थापित किया गया है, जो यात्रियों को आधुनिक, सुविधाजनक एवं सहज यात्रा अनुभव प्रदान कर रहा है। इस सुविधा के माध्यम से यात्रियों को लगभग शून्य प्रतीक्षा समय में कनेक्टिविटी, समर्पित पैसेंजर लाउंज, ऑन-ग्राउंड सहायता तथा नए उपयोगकर्ताओं के लिए पहली यात्रा निःशुल्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अक्टूबर 2025 से अब तक इस पहल के माध्यम से

- 1.5 लाख से अधिक बाइक राइड्स
- 2 लाख से अधिक ऑटो राइड्स
- 1 लाख से अधिक कैब की बुकिंग्स

सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर "Uber Managed Transit Hub" भी शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुव्यवस्थित, सुगम एवं आरामदायक बनाना है। इस हब में समर्पित Uber सहायता कियोस्क, ऑन-ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ, फुट ओवर ब्रिज (FOB) से सीधे जुड़ा एलिवेटेड पार्किंग ज़ोन तथा प्रतिदिन 1.10 लाख से अधिक यात्रियों के लिए व्यवस्थित बोर्डिंग प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सितंबर 2025 से अब तक इस व्यवस्था के माध्यम से 10 लाख से अधिक कैब बुकिंग्स दर्ज की जा चुकी हैं, जो यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं इस पहल की सफलता को दर्शाती हैं।

यात्रियों से मिले उत्साहजनक प्रतिसाद एवं परिचालन सफलता को देखते हुए इस तरह की सुविधाओं का विस्तार अब मणिनगर रेलवे स्टेशन, वटवा रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर भी किया जा रहा है।

यह पहल अहमदाबाद मंडल की स्मार्ट स्टेशन अवसंरचना, तकनीक-आधारित यात्री सेवाओं तथा एकीकृत शहरी मोबिलिटी समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारतीय रेलवे के "Ease of Travel" के विज़न के अनुरूप है।

15 मई से वटवा-मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल का संचालन मणिनगर से होगा

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए से वटवा-मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन मणिनगर स्टेशन से करने का निर्णय लिया गया है। विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09082/09081 मणिनगर-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09082 मणिनगर – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को मणिनगर से 22:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 15 मई, 2026 से 26 जून, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09081 मुंबई सेंट्रल –मणिनगर स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को मुंबई सेंट्रल से 23:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:25 बजे मणिनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 14 मई, 2026 से 25 जून, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहरेगी। यह ट्रेन वटवा स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गर्मियों में पपीता और तरबूज से पाएं प्राकृतिक निखार -शहनाज़ हुसैन

भीषण गर्मी का मौसम केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि त्वचा को भी सबसे अधिक प्रभावित करता है। तेज धूप, गर्म हवाएं, धूल और पसीना त्वचा की प्राकृतिक नमी को कम कर देते हैं, जिससे चेहरा बेजान, रूखा और थका हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसे मौसम में त्वचा को स्वस्थ, ठंडकभरी और चमकदार बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उपाय सबसे अधिक कारगर माने जाते हैं। खासतौर पर पपीता और तरबूज जैसे मौसमी फल त्वचा के लिए किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं हैं। इनमें मौजूद विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और एंजाइम त्वचा को भीतर से पोषण देकर उसे ताजगी और प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं।

प्राकृतिक फलों से किया गया फ्रूट फेशियल आज भी सौंदर्य विशेषज्ञों की पहली पसंद माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक केमिकल का प्रयोग नहीं होता। यही कारण है कि यह हर प्रकार की त्वचा के लिए सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। फ्रूट फेशियल त्वचा की गहराई से सफाई करने के साथ-साथ उसे हाइड्रेट भी करता है। गर्मियों में जब त्वचा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, तब फल आधारित फेस पैक त्वचा को अंदर से नमी और ठंडक प्रदान करते हैं।

पपीता त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी फल माना जाता है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम डेड स्किन को हटाने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही पपीता त्वचा की रंगत को निखारने और दाग-धब्बों को हल्का करने में भी सहायक होता है। यदि पके हुए पपीते की कुछ स्लाइस को मैश करके उसमें चंदन पाउडर, एलोवेरा जेल और गुलाबजल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाए और इसे चेहरे व गर्दन पर आधे घंटे तक लगाया जाए, तो त्वचा में ठंडक और ताजगी महसूस होती है। यह पैक त्वचा को मुलायम बनाकर प्राकृतिक चमक देने में मदद करता है।

पपीते से तैयार एक अन्य फेस पैक भी गर्मियों में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए दो चम्मच मैश किया हुआ पपीता लेकर उसमें दही, शहद और चावल का आटा मिलाया जाता है। यह मिश्रण त्वचा को एक्सफोलिएट करने के साथ-साथ पोषण भी देता है। दही त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है, जबकि शहद प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। चावल का आटा चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है। इस पैक को सप्ताह में दो से तीन बार लगाने से त्वचा में स्पष्ट निखार दिखाई देने लगता है।

गर्मियों में धूप के कारण त्वचा में जलन और सन टैनिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में पपीता और दही का मिश्रण त्वचा को राहत देता है। आधा कप मैश किया हुआ पपीता और दो चम्मच दही मिलाकर तैयार पेस्ट को लगभग 20 मिनट तक चेहरे पर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और चेहरा फ्रेश महसूस होता है। यह फेस पैक त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ उसे स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है।

पपीते में हल्दी मिलाकर तैयार किया गया फेस पैक भी त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हल्दी में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को संक्रमण और पिंपल्स से बचाने में मदद करते हैं। पिसे हुए पपीते में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ और चमकदार बनती है। यह पैक चेहरे की रंगत सुधारने में भी प्रभावी माना जाता है।

तरबूज गर्मियों का सबसे ताजगीभरा फल माना जाता है और यह त्वचा के लिए भी बेहद उपयोगी है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह शरीर और त्वचा दोनों को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। तरबूज का रस प्राकृतिक स्किन टोनर की तरह कार्य करता है। यह त्वचा के रूखेपन को कम कर उसे ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। यदि तरबूज का रस चेहरे पर लगभग 20 मिनट तक लगाया जाए और फिर ठंडे पानी से धो लिया जाए, तो त्वचा को तुरंत फ्रेशनेस महसूस होती है।

तरबूज से तैयार फेस मास्क भी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। बेसन, दूध और तरबूज के रस को मिलाकर तैयार किया गया फेस पैक त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करता है। बेसन त्वचा की गहराई से सफाई करता है, जबकि दूध त्वचा को कोमल बनाता है। तरबूज का रस त्वचा को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाता है। इस फेस पैक के नियमित उपयोग से त्वचा में प्राकृतिक चमक आने लगती है।

तरबूज के छिलके भी त्वचा के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इनके छोटे-छोटे टुकड़ों को चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ने से त्वचा को ठंडक मिलती है और चेहरा ताजा महसूस होता है। यह एक बेहद सरल और प्राकृतिक स्किन केयर उपाय माना जाता है।

गर्मियों में मिश्रित फलों से तैयार फेस मास्क भी त्वचा के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। केला, सेब, पपीता और संतरे जैसे फलों को मिलाकर बनाया गया फेस मास्क त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ डेड स्किन हटाने में भी मदद करता है। यह मास्क सन टैनिंग कम करने और चेहरे की चमक बढ़ाने में सहायक होता है। फलों में मौजूद प्राकृतिक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और युवा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आज के समय में जब लोग केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तब प्राकृतिक फलों से जुड़े घरेलू उपाय फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। पपीता और तरबूज जैसे फल न केवल शरीर को ठंडक देते हैं, बल्कि त्वचा को भी अंदर से स्वस्थ बनाते हैं। नियमित रूप से इन प्राकृतिक फेस पैक्स का उपयोग करने से त्वचा में नमी बनी रहती है, दाग-धब्बे कम होते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक निखार दिखाई देने लगता है।

सौंदर्य विशेषज्ञों का मानना है कि खूबसूरत त्वचा केवल बाहरी देखभाल से नहीं, बल्कि सही खानपान और प्राकृतिक पोषण से भी मिलती है। गर्मियों में ताजे फल खाने के साथ-साथ उनका उपयोग त्वचा पर करना भी बेहद फायदेमंद होता है। यही कारण है कि प्राकृतिक सौंदर्य उपचार आज भी सबसे सुरक्षित और प्रभावी माने जाते हैं।

फियो ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की यूएई और यूरोप की बहु-राष्ट्रीय यात्रा का स्वागत किया, भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई

नई दिल्ली, 12 मई, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने 15-20 मई, 2026 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आगामी आधिकारिक यात्रा का स्वागत किया है। फियो ने कहा कि यह यात्रा प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी को काफी मजबूत करेगी और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है, जब भारत बेहतर व्यापारिक साझेदारियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश-आधारित विकास के माध्यम से यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक एकीकरण को गहरा कर रहा है।

श्री रल्हन ने कहा, " यूएई और प्रमुख यूरोपीय देशों के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की उच्च-स्तरीय वार्ताएं एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार और वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करती हैं। इस यात्रा से इंजीनियरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा होने की उम्मीद है।"

यूएई की प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध तेजी से बढ़ते व्यापार और निवेश संपर्कों के साथ एक मजबूत 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूएई भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक बना हुआ है और मध्य पूर्व तथा अफ्रीका में भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का काम करता है।

उन्होंने आगे कहा, "यह यात्रा भारत-यूएई के आर्थिक संबंधों को विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, बुनियादी ढांचे, निवेश और सेवाओं के व्यापार के क्षेत्रों में और मजबूत करेगी। यूएई में रहने वाला विशाल भारतीय समुदाय भी व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है।"

नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में प्रधानमंत्री की वार्ताओं पर टिप्पणी करते हुए, फियो अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप भारत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात स्थलों और निवेश के स्रोतों में से एक बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हाल ही में संपन्न हुए भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते और भारत-इएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीइपीए) की पृष्ठभूमि में इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

श्री रल्हन ने कहा, "यूरोपीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की चर्चाओं से ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, एआई, इनोवेशन, स्वच्छ तकनीकें, रक्षा निर्माण, ब्लू इकॉनमी, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं और सस्टेनेबिलिटी जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों और उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं।" ओस्लो में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि नॉर्डिक क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तकनीकों, समुद्री क्षेत्रों, डिजिटल इनोवेशन और उन्नत निर्माण में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, "भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ता रणनीतिक तालमेल भारतीय व्यवसायों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी साझेदारियों के लिए नए रास्ते खोल सकता है, साथ ही भारत के सतत और हरित विकास की ओर परिवर्तन में भी सहायता कर सकता है।"

फियो ने उद्योग के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन और भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन सहित प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री की भागीदारी का स्वागत किया और कहा कि इस तरह की बातचीत से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और मजबूत औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्री रल्हन ने आगे कहा, "इस यात्रा के दौरान शामिल देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार सामूहिक रूप से 70 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि इन क्षेत्रों से भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। यह यात्रा द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।"

फियो अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को और बढ़ाएगी, भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करेगी और देश के दीर्घकालिक निर्यात विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देगी।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत : भावनगर मंडल के वेरावल स्टेशन पर नि :शुल्क शीतल पेयजल का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 12 मई, 2026 (मंगलवार) को वेरावल रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वेरावल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण में "रामेश्वर धुन मंडल/रामेश्वर महिला सतसंग मंडल, हरसिध्धी सोसायटी, वेरावल" का सहयोग रहा। उपरोक्त संस्था के सदस्यों ने यात्रियों हेतु ठंडा पानी की व्यवस्था की।

स्टेशन पर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

साबरमती रेलवे स्टेशन पर DRM ने खुद चलाई बुलडोजर, यात्रियों के लिए दो मंजिला आधुनिक 'होल्डिंग एरिया' का भूमि पूजन, यात्रियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन को मिलेगा नया आयाम

साबरमती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज दो मंजिला अत्याधुनिक "होल्डिंग एरिया" के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश द्वारा प्रतीकात्मक रूप से बुलडोजर चलाकर परियोजना कार्य का शुभारंभ किया गया।

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देशभर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 76 यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विकसित होल्डिंग एरिया की सफलता के पश्चात अब साबरमती स्टेशन पर भी यह आधुनिक सुविधा विकसित की जा रही है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि साबरमती

स्टेशन के पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। इसी क्रम में स्टेशन परिसर में लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विशाल दो मंजिला होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मंजिल 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित होगी।

उन्होंने बताया कि इस आधुनिक होल्डिंग एरिया में लगभग 8,000 से 10,000 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी, जिससे होली पूर्व, दीपावली छठ, खाटूश्याम सहित धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की भीड़भाड़ की स्थिति में यात्रियों के आवागमन एवं प्रबंधन को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

नवनिर्मित होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, जलपान केंद्र तथा पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए पृथक शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यात्रियों की सुरक्षा एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु स्टेशन पर अत्याधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। टिकट जांच मार्ग पर आधुनिक लगेज स्कैनर एवं प्रतिबंधित सामान की पहचान करने वाले विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही प्लेटफॉर्म एवं रूफ प्लाज़ा तक सुगम पहुंच के लिए पर्याप्त संख्या में एस्केलेटर, लिफ्ट एवं सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी।

इसके अतिरिक्त एक नए फुट ओवरब्रिज (FOB) का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी सीधे होल्डिंग एरिया से रहेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

इस अवसर पर मुख्य परियोजना प्रबंधक (RLDA) श्री संजीव कुमार, डीजीएम (RLDA) श्री अर्पण अवस्थी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) श्री वैभव सकलेचा, वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त, श्री अंशुमान त्रिपाठी सहित रेलवे एवं RLDA के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।